

RAJYA SABHA

Thursday, 10th December, 1970/the 19th Agrayana, 1892 (Saka) The House met at eleven of the clock, MR. CHAIRMAN in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

कालीन के पुष्ते के निर्यात में कमी

*606. श्री आर० पी० खैतान : †
श्री सोताराम जैपुरिया :

क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जूट माल और विशेष रूप से कालीन के पुष्ते के निर्यात में दिन प्रति दिन कमी होती जा रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस वर्ष इस मद के निर्यात में भारत में कहां तक विश्व मंडी खोती है ; और

(ग) हमारे जूट माल के लिए विदेशी मंडियों पर कब्जा प्राप्त करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

i [DECLINE IN EXPORT OF CARPETS]

606. SHRI R. P. KHAITAN:
SHRI SOTARAM JAIPURIA:
Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state:

whether it is a fact that the export of jute goods and particularly of carpets is declining day by day;

(b) if so, to what extent India has lost world market in the export of this item this year; and

(c) what steps are being taken by Government to capture foreign markets for our jute goods?

The question was actually asked on the floor of the House by Shri R. Khaitan.

[English translation.

1595 RSD—1.

विदेशी व्यापार उपमंत्री (श्री श्री राम सेवक) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

हाल ही के वर्षों में पटसन के माल (कालीन अस्तर को छोड़ कर) के निर्यातों में निम्नलिखित कारणों से गिरावट आई है :

(1) पाकिस्तान में, जहां निर्यातकों को वोलम वाउचर का लाभ प्राप्त है, प्रतिशोभिता, (2) संश्लिष्ट माल में प्रतिशोभिता, (3) विपुल परिमाण में माल भरने भेजने की पद्धति के कारण पटसन माल की विश्व मांग में कमी, (4) बेहतर गुण के कच्चे माल की कमी (5), श्रीमकों द्वारा गड़बड़ तथा और हड़तालें (6) कतिपय देशों, मुख्यतः दक्षिण दक्षिण पूर्व एशिया तथा अफ्रीका में पटसन मिलों की स्थापना। फिर भी कालीन अस्तर के निर्यातों में तेजी से वृद्धि हुई है, परन्तु हाल ही के कुछ महिनों में गिरावट आ गई है। इसका कारण इस मद के विशालतम बाजार-संयुक्त राज्य अमरीका में मन्दी का होना है।

अप्रैल-सितम्बर, 1970 में पटसन के माल के निर्यातों का परिमाण गत वर्ष की उसी अवधि की तुलना में 65,000 मेट्रिक टन कम रहा। इसका कारण काफी हद तक संयुक्त राज्य अमरीका में मन्दी, जिससे कालीन अस्तर की खरीदारी पर कूप्रभाव पड़ा और कलकत्ता पत्तन पर नाविकों की लम्बी हड़ताल है।

कालीन अस्तर की मांग पुनः होने लगी है और आशा है कि कालीन अस्तर के भारत के निर्यात पुनः बढ़ेंगे और उनमें हर महीने सुधार होता रहेगा। कालीन अस्तर का उत्पादन तथा निर्यात बढ़ाने के लिये औद्योगिक वित्त निगम के माध्यम से पटसन मिलों को व्याज की रियायती दरों पर ऋण महायत्ना

दी जा रही है। सरकार स्थिति की निरन्तर समीक्षा करती रहती है और निर्यात बढ़ाने के लिये हर तरह से कोशिश की जाती है।

[THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (CHOWDHARY RAM SEWAK): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

In recent years, exports of jute goods (other than carpet backing) have declined on account of factors such as (i) competition from Pakistan where exporters get the benefit of bonus vouchers, (ii) competition from synthetics, (iii) shrinkage of world demand for jute goods due to heavy in-roads by bulk handling, (iv) raw material deficiency in superior quality (v) labour unrest and strikes and (vi) emergence of jute mills in certain countries mainly in South East Asia, Africa. Exports of carpet backing in South East Asia, had, however, increased rapidly but showed a decline in recent months due to recession in U.S.A. which is the largest market for this item.

Exports of jute goods during the period April-September, 1970 fall short by 65,000 tonnes of the quantity exported during the same period last year. This was largely due to the recession in the U.S.A. which affected off take of carpet backing and the prolonged strike by bargemen at Calcutta port.

Demand for carpet backing is now reviving and it is expected that India's exports of carpet backing will pick up again and improve month by month. In order to increase production and exports of carpet backing loan assistance at concessional rate of interest is being extended to jute mills

[T] English translation.

through the Industrial Finance Corporation. Government are keeping the position under constant review and every endeavour is made to step up exports.]

श्री आर० पी० खेतान : मंत्री जी ने यह स्टेटमेंट दिया है जूट एक्सपोर्ट के बारे में, जूट के प्रोडक्शन के बारे में। तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि किन कारणों से एक्सपोर्ट कम हुआ है और उसके लिए आप क्या-क्या उपाय कर रहे हैं? अभी भी आप देखते हैं कि स्ट्राइक चल रही है। उसका नोटिस पहले भी दिया गया था, अभी तक स्ट्राइक समाप्त नहीं हुई है, उसको रोकने के वास्ते आप क्या कर रहे हैं?

श्रीधर राम सेवक : जहाँ तक एक्सपोर्ट प्रमोशन और प्रोडक्शन का सवाल है, उसके लिए हमने विभिन्न तरीके इस्तेमाल किए हैं— Improved method of cultivation to increase the production of raw jute, soft loans to the industry, higher development rebate in Income-tax, etc. and export duty rebate, etc.

जहाँ तक स्ट्राइक का प्रश्न है, उसके लिए अभी भी बातचीत चल रही है और आज भी दोनों सूप्स हमारे यहाँ मिल रहे हैं और हमको आशा है कि स्ट्राइक खत्म होने में हम सहयोग दे सकेंगे।

श्री आर० पी० खेतान : आपने कहा है कि पाकिस्तान बाउचर दे रहा है और अमरीका में सिन्थेटिक इसका कम्पटीटर हो रहा है। ऐसी हालत में हमारे यहाँ एक्सपोर्ट इयूटी लगी हुई है, हम कम्पटीशन में चल नहीं सकते। तो इसके बारे में गवर्नमेंट क्या कर रही है?

श्रीधर राम सेवक : एक्सपोर्ट इयूटी में श्रीमन्, हमने पिछली बार कन्सेशन दिया था और वह कन्सेशन यह था कि पर टन कार्पेट बैकिंग में 300 रुपए, हैसियन में 200 रुपए और सैकिंग में 150 रुपए की छूट

हो गई और कुछ आइटम तो ऐसे थे, जिन पर इयूटी बिल्कुल एवालिज कर दी, जैसे काटन बॉकिंग और बूल सैक ।

श्री सुन्दर सिंह भण्डारी : श्रीमन्, जैसा मंत्री जी न बताया, श्रमिकों के प्रति-निधियों से इस उद्देश्य के सम्बन्ध में आपकी बातचीत चल रही है । मैं जानना चाहता हूँ कि किस रूप में इस उद्देश्य से आपका सम्बन्ध आया है ? दूसरे इस उद्देश्य के कारण श्रमिकों की जो माँग आई ० जे० एम० ए० मालिकों से मजदूरी की बातें चली हैं, उनका सीधा सम्बन्ध जूट के एक्सपोर्ट ट्रेड की पारि-वर्लिटीज और मार्केटिंग की सुविधा को दृष्टि से जुड़ा हुआ है । मजदूरों की उचित माँगें मानी जायें, परन्तु जूट को एक्सपोर्ट विलिटी पर अस्तर न पड़े, इन दोनों बातों को ध्यान रखते हुए एक्सपोर्ट इयूटी या इस प्रकार की किसी और चीज पर भी आप इस समय विचार कर रहे हैं ?

श्री ललित नारायण मिश्र : माननीय सदस्य ने कल भी इस तरह का सवाल किया था, यहां की प्रोसीडिंग्स से मुझे मालूम हुआ ।

श्री सुन्दर सिंह भण्डारी : लेकिन वह तो टाल गये ।

श्री ललित नारायण मिश्र : माननीय सदस्य को ज्ञान होगा कि जूट टैक्सटाइल की जो इ इस्ट्री है, उसमें केवल एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का ही नहीं, इन्डस्ट्री का व्यवसाय का सम्बन्ध भी इस मंत्रालय से है । इसी हक से हम लोगों ने हस्तक्षेप किया है । सम्बद्ध लोगों की बैठक हो रही है, कल भी हुई है, आज अभी भी चल रही है । मुझे अन्दाजा है कि कुछ समझौता निकल आयेगा । खूना की बात है कि मजदूर लोग भी और मालिक लोग भी, मैनेजमेंट भी, इस बात को समझते हैं कि हम लोग 60 लाख रुपए प्रति दिन फारेन एक्सचेंज का इसकी वजह से नुकसान उठा रहे हैं ।

जहां तक एक्सपोर्ट इयूटी की बात का सम्बन्ध है, पिछले बजट में इयूटी कम की गई थी, अभी इयूटी कम करने की कोई भी बात नहीं है ।

SHRIA. G. KULKARNI: Sir, is it not a fact that the jute textile industry is interested in the domestic market more than in the export. In this connection, may I particularly draw the attention of the hon. Minister that speculation is going on and is allowed under the forward market. Unless it is banned, the domestic market would not be available to the jute industry and they will not be able to export? That is number one. Secondly, Sir, would the Government not think that more research and development is necessary for making our jute carpet backing and goods more popular in foreign countries, particularly in the U.S.A., where carpets of length-to-length are required and synthetic backing is much preferable due to fire hazard?

SHRI L. N. MISHRA: Sir, this has been the difficulty that the jute textile industry relies more on indigenous consumption, because it saves them from many difficulties. But we are keen that we should export it more, because jute is one of the industries which are perhaps the top-most foreign exchange earners.

About speculation. Sir, it is the function of the Ministry of Industrial Development. We have not thought much about it. But we will have to think of doing something as we have done in the case of 'kapas'. If the situation further deteriorates, we will have to think of this measure of banning also. After all, apart from the industry, we have to look after the interests of the growers also.

About research, it is a fact that we have to do a lot of research work, so far as the quality of jute is concerned. The quality of jute is much worse. We have to improve the quality of jute. For that a separate allotment

by the Planning Commission has been made and we are approaching the Planning Commission and the Finance Ministry to get more allotment to improve the yield of jute per acre and also the quality.

SHRI CHITTA BASU: May I know from the hon. Minister whether it is not a fact that due to the lack of interest by the Foreign Trade Ministry in the matter of settling dispute between the IJMA and the jute manufacturers in West Bengal ultimately the jute strike had taken place? Does he agree that the demands of the jute workers, particularly in regard to the security of service and also the demand for bonus, are justified? If so, will he also impress upon the IJMA in accede to their demands and thereby improve the conditions of the working of the jute industry as a whole so that we may not be deprived of the foreign exchange? At what stage does the matter of conciliation rest? Also, will the hon. Minister assure the House that if the IJMA does not agree with his proposals, the Ministry will withhold the sanction of 44 crores of rupees, to which they have agreed for the modernisation of the industry?

SHRI L. N. MISHRA: Sir, It is not a fact that the Ministry did not take interest in solving this industrial dispute. The first meeting was convened by the Ministry of Labour and Employment, and our officers were present there. And I was also present in Delhi and was in constant touch with them. If my presence was required in the meeting, I would have been there. The senior officers dealing with the jute work were there. After that I had myself seen both the parties for 8 hours on the first day and, for 2 hours on the second day. Today also I had a meeting with the labour representatives. We are very keen that the strike would end. About the demands it will not be advisable nor proper to say about *badli* or bonus or gratuity here. These are problems which are being taken up in the nego-

tations that are going on in our Ministry. About withholding Rs. 44 crores, I will not agree since this allotment has been made to modernise the industry so that we are in a position to compete in the world where we have tough competition from Pakistan and a few other countries.

607. [Transferred to the 18th December, 1970.]

U.S. WITHDRAWAL FROM INTERNATIONAL COFFEE AGREEMENT

608. SHRI KRISHAN KANT: SHRI ARJUN ARORA: DR. SALIG RAM: SHRI RAJENDRA PRATAP SINHA:

Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the growth of a lobby in the U.S.A. advocating withdrawal of that country from the International Coffee Agreement; and

(b) if so, whether the Government of India have assessed the consequential effect on our exports of Coffee?

THE MINISTER OF FOREIGN TRADE (SHRI L. N. MISHRA): (a) Yes, Sir. The House Ways & Means Committee of U.S.A. has, however, voted to extend U.S. participation in the Agreement until July 1, 1971.

(b) Does not arise.

SHRI KRISHAN KANT: What attempt the Government of India is making so that we can export more to the US? How much coffee is exported to the Soviet Union and what arrangements have been made? The price of coffee during the last year has risen because the cost of living of living index has also risen. What attempt the Government has to in-

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Krishan Kant.